www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 29 मई 2019

दैनिक जागरण

आप अज्ञानी हैं, यह जानना ज्ञान की दिशा में एक बड़ा कदम है

पाकिस्तान को संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथग्रहण समारोह में पिछली बार की तरह दक्षेस देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करने के बजाय बिम्सटेक देशों के शासकों को निमंत्रण भेजकर एक तीर से दो निशाने साधने वाला काम किया है। बिम्सटेक देशों की ओर हाथ बढ़ाकर एक तो उन्होंने इस सवाल के लिए गुंजाइश नहीं रखी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया और दूसरे, करीब-करीब उन सभी देशों को मैत्री संदेश भी दे दिया जो दक्षेस के सदस्य हैं। बिम्सटेक में पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षेस के अन्य सभी देश शामिल हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की प्रत्यक्ष अनदेखी किए बिना उसे यह संदेश भी दे दिया कि अभी हालात ऐसे नहीं कि उस पर भरोसा किया जा सके। जहां तक अफगानिस्तान और मालदीव की बात है तो यह किसी से छिपा नहीं कि इन दोनों देशों से भारत के रिश्ते बहुत मधुर हैं और आने वाले समय में यह मधुरता बढ़नी ही है। माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश दौरे में मालदीव जा सकते हैं। बिम्सटेक देशों के अतिरिक्त किर्गिस्तान और मॉरीशस के शासनाध्यक्ष भी निमंत्रित किए गए हैं तो एक्ट एशिया नीति के तहत ही। भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान चाहे जो प्रतिक्रिया दे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह अपने उसी पुराने रुख पर कायम दिख रहा है जिसके तहत वह कश्मीर में दखल जारी रखते हुए भारत से सभी मसलों पर बात करना चाह रहा है। इस चाहत की एक वजह भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करना भी है ताकि खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा दिया जा सके।

पाकिस्तान पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो इसके स्पष्ट संकेत नहीं कि उसने उन आतंकी तत्वों पर सचमुच लगाम लगाई है जो भारत के लिए खतरा बने हुए हैं और दूसरे, वह बालाकोट हमले के इतने दिन बाद भी अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित किए हुए है। हैरत नहीं कि किस्म-किस्म के आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की उसकी घोषणा का मकसद भी केवल अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ की काली सूची में आने से बचना हो। पाकिस्तान से ऐसे किसी आधार पर बात शुरू करने का कोई औचित्य नहीं कि आम चुनाव संपन्न हो गए हैं और खुद इमरान खान यह मान रहे थे कि मोदी के सत्ता में लौटने पर ही दोनों देशों में वार्ता संभव है। निःसंदेह पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए गए थे और खासकर जिस तरह बालाकोट में आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त करने का पराक्रम किया गया उसका उस पर असर तो पड़ा है, लेकिन इसका भरोसा नहीं कि वह फिर कब पुरानी हरकतों में लिप्त हो जाए। पाकिस्तान ने भारत को इतने धोखे दिए हैं कि अब उस पर आसानी से भरोसा न करने में ही समझदारी है। मोदी को मिला जनादेश भी पाकिस्तान से तत्काल बात शुरू करने की जरूरत रेखांकित नहीं करता। निःसंदेह इस तथ्य को भी ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि इमरान खान अपनी उस सेना के रहमोकरम पर हैं जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है और जो कश्मीर पर नजरें भी गड़ाए हुए है।

गिरफ्तारी की तलवार

सारधा चिटफंड कांड में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं वर्तमान में एडीजी सीआइडी राजीव कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआइ सारधा कांड के सुबूत मिटाने के मामले में जिस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है उस जाल में राजीव कुमार पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस के साथ-साथ सीबीआइ के समक्ष हाजिर होने का समन भी जारी हो चुका है। हालांकि वे सीबीआइ के समक्ष सोमवार को पेश नहीं हुए। छुट्टी पर होने की वजह बताते हुए सीबीआइ से और वक्त मांगा है। राजीव का पत्र लेकर सीआइडी के अधिकारी सोमवार को सीबीआइ दफ्तर पहुंचे थे। पत्र में लिखा है कि वह तीन दिनों की छुट्टी पर हैं इसीलिए वह फिलहाल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो पाएंगे। यहां बताना आवश्यक है कि कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा चुका है। उन्हें निचली अदालत या फिर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी नहीं मिली है। ऐसे में यदि वे सीबीआइ दफ्तर में हाजिर होते तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था। सीबीआइ अधिकारियों का मानना है कि वे इसीलिए हाजिर नहीं हो रहे हैं कि तीन दिनों में अग्रिम जमानत का प्रबंध हो जाए। रविवार को सबसे पहले सीबीआइ ने पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। इसके बाद फोन पर लगातार संपर्क की कोशिश की थी, लेकिन संपर्क नहीं होने पर सीबीआइ अधिकारी ने उनके लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर जाकर समन दिया और सोमवार को दस बजे से पहले सीबीआइ दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया था, परंतु सोमवार को उन्होंने हाजिर न हो कर पत्र भेजा। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कुमार से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यदि राजीव कुमार की गिरफ्तारी हो जाती है तो बंगाल सरकार और खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वह राजीव कुमार से पूछताछ के विरोध में धरना पर बैठ गई थीं।

ऐतिहासिक कायाकल्प का पड़ाव

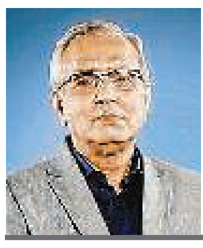

राजीव कुमार

अभी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन प्रचंड जनादेश ने यह दिखाया कि भारतीय मतदाता सरकार पर यह भरोसा कर रहे हैं कि वह उनके हित में ईमानदारी से काम करेगी

नरेंद्र मोदी को अभूतपूर्व बहुमत देने में भारतीयों ने विलक्षण परिपक्वता और दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया है। यह उन तीन राज्यों में भाजपा द्वारा विपक्ष का सूपड़ा साफ करने से भी झलकता है जहां वह बीते दिसंबर में चुनाव हार गई थी। मतदाताओं ने दर्शाया कि वे राष्ट्रीय और प्रांतीय मुद्दों में अंतर कर सकते हैं और उन्हें नेतृत्व की गुणवत्ता का भी बखूबी अहसास है। पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के आधार पर लोगों ने उन पर फिर से अपना भरोसा व्यक्त किया। लोगों ने यह महसूस किया कि मोदी ने समाज के सबसे निचले तबके के जीवन में सुधार के लिए हरसंभव प्रयास किए। इससे लोगों में भरोसे का भाव भी बढ़ा और उन्होंने मोदी को खुला हाथ दिया ताकि वह देश को अपने हिसाब से आगे ले जा सकें।

इससे पहले भारतीय जनता ने देश के राजनीतिक नेतृत्व में ऐसी आस्था 1965 में व्यक्त की थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दोहरे आह्वान पर देश एकमत हो गया था। शास्त्री ने एक तो युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए लोगों से अपने पुश्तैनी जेवर दान देने की अपील की थी और दूसरे यह अनुरोध किया था कि एक सप्ताह में एक दिन एक वक्त के खाने में अनाज को छोड़ दें ताकि अमेरिकी आयात पर हमारी निर्भरता घट सके। करीब आधी सदी बाद हमने राजनीतिक वर्ग को लेकर निराशावाद की आम धारणा को उलट दिया और उसमें भरोसा बहाल किया। हमारे लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आदर्श और प्रतिभाशाली युवा इससे राजनीतिक क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे और आने वाले दशकों में वे वैश्विक पटल पर भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकेंगे।

राजनीतिक नेतृत्व में जनता के भरोसे की बहाली के साथ ही और भी शक्तिशाली संदेश मिले हैं। एक तो यही कि अब शासक और शासित के बीच कोई अंतर नहीं रह गया है। पहले अंतर वाली ही परंपरा थी और इसे दिल्ली के पश्चिमी ढर्रे वाले अभिजात्य वर्ग ने पोषित किया था। इसी वर्ग के सदस्यों ने देश की राजनीति, नौकरशाही, न्यायिक और यहां तक कि नागरिक संगठनों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। मोदी को जिस विश्वास और भरोसे के साथ दिल खोलकर बहुमत दिया गया उससे यह कुलीन वर्ग, जिसे अमूमन लुटियंस समूह या खान मार्केट गिरोह के रूप में जाना जाता है, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। प्रधानमंत्री शासन को जिस तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश में जुटे हैं और जिस तरह जनता से प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं उससे नए भारत के नागरिकों ने यह भरोसा करना भी शुरू कर दिया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण और देश के आर्थिक विकास में राजनीतिक वर्ग के साथ मिलकर योगदान दे सकते हैं। दिल्ली के मीडिया के एक बड़े हिस्से और कुलीन वर्ग को भले ही यह नजर न आए, लेकिन जमीनी स्तर पर यही भावना बलवती हुई है कि मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि विकास का फल निरंतरता के साथ सभी के पास पहुंचेगा।

अवधेश राजपूत

विकास को जन आंदोलन बनाने के लिए यह एक बुनियादी शर्त है।

हम सभी भारतीय, यहां तक कि वंचित वर्ग के लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर विकास और वृद्धि में योगदान करने की उम्मीद और प्रयास कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मायने यही रखता है कि हम अपना काम करते हुए राष्ट्र निर्माण में तत्पर रहें। अब 'माइ बाप सरकार' वाली नकारात्मक व्यवस्था पर निर्भर रहने के दिन बीत गए, जिसे कुछ कुलीन वर्गों ने अपनी थाती बना लिया था। अब भारतीयों ने विकास को अपनी खुद की मुहिम बना लिया है और वे चाहे जिस पेशे में हों, अपने-अपने स्तर पर इस अभियान में योगदान दे रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक कायाकल्प का पड़ाव है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंची वृद्धि के दौर में दाखिल करेगा और यह तेज वृद्धि आने वाले दशकों में भी कायम रहेगी।

अगर राष्ट्रीय लक्ष्यों की बात करें तो यह वर्ष 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 'भारत छोड़ो' आंदोलन और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1965 में एक वक्त के भोजन का त्याग करने की अपील वाले वक्त जैसा है। इसमें सभी भारतीय अपनी प्रतिभा, समझ और नए तौर-तरीकों वाली क्षमता के साथ न केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि देश मध्यम आय के दायरे से बाहर निकल आए, बल्कि तेजी से आगे बढ़ते हुए उस समय तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए जिस समय हम अपनी आजादी की सौवीं वर्षगांठ मना रहे हों।

राजग के नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे साफ तौर पर कहा कि वे शासक वाले रवैये का परित्याग करें। इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के बीच भरोसा बढ़ेगा। अगला लक्ष्य नौकरशाही में भी यही भाव लाना और अंततः उपनिवेशवादी विरासत का परित्याग करना होना चाहिए। नौकरशाही की जवाबदेही परिणामों पर आधारित होनी चाहिए। इससे ही नौकरशाही शासक वर्ग की मानसिकता से बाहर आएगी और टैक्स चुकाने वाले उन लोगों के प्रति और जिम्मेदार बनेगी जिनके पैसे से वह चलती है। अपने इसी संबोधन में प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने, विकास में भागीदार बनाने और उन्हें डराकर रखने वालों से मुक्त करने की भी बात कही। यह सबका साथ सबका विकास नारे का स्वाभाविक विस्तार है। इसके लिए जमीनी स्तर पर गंभीरता से कोशिश करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज का कोई भी तबका विकास प्रक्रिया से अछूता न रहे। अच्छी बात यह है कि बीते पांच सालों में सबको समाहित करने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं ने सब तक अपनी पहुंच बनाई है।

इन योजनाओं के तहत 35 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुले हैं। नौ करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं। 714 जिलों में सात करोड़ से अधिक रसोई गैस सिलेंडर बंटे हैं। इसके अलावा महज सात माह में तीस लाख लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। इन योजनाओं की सफलता ने भरोसे की बुनियाद मजबूत की है। यह एक बड़ा बदलाव है और इसने सरकार और उसके वायदों को लेकर आम आदमी की सोच को बदला है। आखिरकार भारत उन देशों में शामिल होगा जो अपने लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए जाने जाते हैं। निःसंदेह अभी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन प्रचंड जनादेश ने यह दिखाया है कि भारतीय मतदाता इस पर यकीन कर रहे हैं कि एक व्यापक बदलाव आया है और सरकार पर यह भरोसा कर रहे हैं कि वह उनके हित में ईमानदारी से काम करेगी। यह कायाकल्प इस बात को सुनिश्चित करेगा कि यह सदी भारत की होगी।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

हुआ तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ

राजीव सचान

राहुल गांधी को यह देखना ही होगा कि वे तमाम फैसले किसने लिए जिनकी वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया?

पांच साल विपक्ष में रहने, सत्ता विरोधी प्रभाव का लाभ उठाने और मोदी सरकार की चौतरफा घेराबंदी करने के बाद भी अगर कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले इस बार केवल आठ सीटें ही अधिक पा सकी तो यह हर लिहाज से करारी हार है। इस हार के बाद पार्टी में हाहाकार मचना ही था, सो मचा हुआ है। यह मचना भी चाहिए। कांग्रेस में हाहाकार की खबरों के बीच राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े बताए जा रहे हैं। इस्तीफे की उनकी पेशकश के बाद कांग्रेस के अन्य अनेक नेता भी इस्तीफा देने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। पता नहीं इन इस्तीफों का क्या होगा, लेकिन जिस तरह पराजय के मूल कारणों की तह में जाए बिना राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य कांग्रेसी नेता कुर्बानी देने को तैयार दिख रहे हैं उससे यह नहीं लगता कि पार्टी का भला होने वाला है। राहुल गांधी अपने तीन वरिष्ठ नेताओं-पी चिदंबरम, अशोक गहलोत और कमलनाथ से इसलिए खफा बताए जा रहे हैं कि उन्होंने उनके इन्कार के बावजूद अपने बेटों के लिए टिकट ले लिया और फिर उन्हें जिताने में ऐसा जुटे कि पार्टी की सुध लेना ही भूल गए। आखिर जब राहुल गांधी यह जान रहे थे कि ये पिताजी अपने बेटों की किस्मत चमकाने में व्यस्त हो जाएंगे तब फिर उन्होंने चिदंबरम, गहलोत और कमलनाथ के बेटों को टिकट दिया ही क्यों? क्या राहुल गांधी इसलिए अपने रुख पर कायम नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने खुद बहन प्रियंका को सीधे महासचिव बनाकर कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय कर दिया था? वह शायद इसलिए भी ज्यादा जोर देकर इन नेताओं के बेटों को टिकट देने से इन्कार न कर सके हों, क्योंकि उन्हें यह अहसास हो कि वह भी तो सोनिया गांधी के बेटे होने के कारण ही कांग्रेस अध्यक्ष बन सके हैं। सच्चाई जो भी हो, चिदंबरम, अशोक गहलोत और कमलनाथ के बेटों के टिकट उन्हीं दिनों पक्के हुए होंगे जब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के टिकट कटने पर कांग्रेस के नेता भाजपा को यह ताना देने में लगे हुए थे कि वह अपने बुजुर्ग नेताओं का सम्मान नहीं करती।

कांगेस भाजपा से कुछ सीखे या नहीं, लेकिन उसे यह तो समझना ही चाहिए कि संस्थाएं चाहे राजनीतिक हों या गैर राजनीतिक, वे दृढ़ फैसलों से ही चलती हैं। संस्था संचालक को विनम्र होना चाहिए, लेकिन उसे फैसला लेते समय दृढ़ता दिखानी चाहिए। बेशक राहुल गांधी विनम्र और सरल स्वभाव के हैं, लेकिन वह तब बहुत अहंकारी और अशालीन दिखते थे जब मोदी के प्रति अपनी हिकारत का प्रदर्शन करते हुए अपना प्रिय नारा-चौकीदार चोर है उछालते थे। बेहतर हो राहुल गांधी किसी से और हो सके तो कांगेस की सोशल मीडिया प्रभारी से पता कराएं कि इस अभद्र नारे ने कांग्रेस का कितना भला किया? यह एक भद्दा नारा था और राहुल गांधी के मुख से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों को जनता का आदेश मानते हुए कांग्रेस की पराजय विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर एक परिपक्व नेता जैसा व्यवहार किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है और वह यह लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन आखिर कौन सी विचारधारा? क्या वही जिसके तहत राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार को सहारा देने जेएनयू चले गए थे? यह वही कन्हैया कुमार हैं जिन्हें बिहार के महागठबंधन में स्थान न मिलने पर दिग्विजय सिंह ने अफसोस जताया और ससम्मान भोपाल आमंत्रित किया। कन्हैया तो भोपाल में प्रकट नहीं हुए, लेकिन गुजरात में कांग्रेस के सिपाही जिग्नेश मेवानी बेगूसराय जाकर लाडले कन्हैया को गले लगाते अवश्य दिखे। जिग्नेश दिल्ली में भी दिखे, लेकिन कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए।

क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा के तहत ही बालकोट हमले के सुबूत मांग रही थी और इमरान खान पर बुरी तरह फिदा नवजोत सिंह सिद्धू को देश भर में घुमा रही थी, लेकिन अपने सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पंजाब में ही सीमित करना उचित समझ रही थी? क्या पार्टी की विचारधारा को बल देने के लिए ही राहुल गांधी ने केरल की वह सीट चुनी जहां कांगेस की सहयोगी मुस्लिम लीग का दबदबा है? आखिर कांग्रेस की विचारधारा में ऐसा क्या जुड़ा या घटा जिसके चलते राज ठाकरे से लेकर प्रशांत भूषण जैसे लोग राहुल गांधी के मुरीद बनकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में जुट गए थे? आखिर शत्रुघ्न सिन्हा को यह सुविधा किसने दी कि वह अपनी मनचाही सीट से खुद खड़े हो जाएं और पत्नी को लखनऊ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दें? जब शत्रुघ्न सिन्हा को यह सुविधा दी जा रही थी तब पार्टी ने खामोश रहना जरूरी क्यों समझा? ऐसे विचित्र फैसलों पर लोग हंसते नहीं तो क्या यह कहते कि राहुल जी ने शानदार दांव चला है।

आखिर पार्टी के भीतर यह विचार कहां से आया कि तीन राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस को न केवल ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, बल्कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50 फीसद करने की मांग कर रहे दलों की पैरवी अपने वकील नेता से करानी चाहिए? एक सवाल यह भी कि कांग्रेस के वकील नेताओं को तीन तलाक और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर पार्टी की जड़ें खोदने वाली दलीलें देते देखकर किसी कांग्रेसी को यह आभास क्यों नहीं हुआ कि इससे जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है? जो लोग भी यह कहकर राहुल गांधी की पीठ थपथपा रहे कि चुनावों में उन्होंने बड़ी मेहनत की वे अगर उनके शत्रु नहीं तो मित्र भी नहीं, क्योंकि मेहनत तो अरविंद केजरीवाल ने भी की और तेजस्वी यादव ने भी। अगर कोई नेता जनता के मर्म को छूने और जमीनी हकीकत भांपने में नाकाम रहता है तो फिर कितनी भी मेहनत कर ले और कैसे भी नारे गढ़ ले उसे कुछ हासिल नहीं होता। यह राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि यह विचार किसका था कि आनन-फानन न्याय नामक योजना की घोषणा कर दो और जब सवाल उठे कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा तो आप कह देना, अनिल अंबानी की जेब से और सैम पित्रोदा से कहलवा देना, स्वार्थी मध्यवर्ग से। क्या इतनी गंभीर गलतियां करने वाला कोई दल जनता का भरोसा हासिल कर सकता है? पता नहीं राहुल गांधी क्या करेंगे, लेकिन अगर राजनीति उनके मिजाज में नहीं है तो उन्हें और मुश्किल पेश आ सकती है। उन्हें कोई भी फैसला लेने के पहले यह तो देखना ही चाहिए कि वे तमाम फैसले किसने लिए जिनकी वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समर्पण

खुद की काबिलियत पर संदेह करना मानव की स्वाभाविक कमजोरियों में शुमार किया जाता है। मानव जीवन का यह अवगुण उसे अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की राह में सबसे बड़े अवरोध के रूप में काम करता है, क्योंकि जब हम खुद ही अपनी क्षमता के बारे में विश्वस्त नहीं होते हैं तो कामयाबियों के सफर में हम बड़ी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसी दशा में हमारे बढ़े हुए कदम सहसा ठहर जाते हैं और शिद्दत से देखे हुए सपनों का हम खुद ही गला घोंट देते हैं। सोच कर देखिए कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं या फिर करने की योजना बना रहे हैं और उसी के बारे में आपको यह दुविधा सता रही हो कि इस कार्य में आप सफल भी होंगे या नहीं तो फिर हम केवल अपने अमूल्य समय की ही बर्बादी कर रहे होते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हमें अपने लक्ष्यों तथा सपनों के प्रति पूरी तरह से समर्पित तथा निष्ठावान होना चाहिए और मन में हमेशा यह अडिग विश्वास रखना चाहिए कि खुद में अंतर्निहित क्षमता के फलस्वरूप हम अपने प्रयास और प्रयोजन में अवश्य ही सफल होंगे।

सच पूछिए तो यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमारे जीवन में दुविधा ही क्यों उत्पन्न होती हैं? इस सत्य से इन्कार करना कदाचित आसान नहीं होगा कि दुविधाएं या संशय आत्मविश्वास में कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। जब हमें यह लगता है कि हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सफल होना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य योग्यता का अभाव है तो हमारे पैर उस राह में डगमगाने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। फिर हम उन सपनों को साकार करने की कोशिश तो करते हैं, किंतु उसके लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार हमारे संसाधन और बेशकीमती समय बिना किसी उपलब्धि के बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा हम अपने जीवन का जो भी लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लें तो फिर उसके बाद उसके प्राप्त होने के बारे में कभी भी मन में किसी संदेह या नकारात्मक विचार को जन्म नहीं दें। खुद की क्षमता में अटूट विश्वास रखें और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, परंतु इसके लिए सभी आवश्यक सूत्रों को आत्मसात करना होगा।

श्रीप्रकाश शर्मा

आत्ममंथन का समय

फिर से

अब नेताओं से पांच साल बाद ही मुलाकात होगी। तब तक जनता के लिए आत्ममंथन का समय है कि जिन्हें आदेश दिया है उनका क्या कहर बरपेगा?

चुनाव परिणाम आ गए हैं। जनता ने अपना आदेश दे दिया है। टीवी पर तो सभी नेताओं ने इसे जनादेश कहते हुए सर माथे से लगा लिया है। यही एक मात्र दिन होता है जब जनता को आदेश देने की अनुमति होती है। इसके बाद पांच साल तक वह इस गुस्ताखी की सजा काटती है।

तिवारी जी और घंसु ने भी इसी परंपरा का पालन करते हुए जनादेश का स्वागत किया। दोनों हार गए हैं। दो लोगों वाली नई-नई बनी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी नेस्तनाबूद हो गई है। शाम आत्ममंथन के लिए बैठक बुलाई गई पान की दुकान के पीछे पुलिया पर। आत्ममंथन शुरू हुआ। दोनों ने ही हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। घंसु को दो वोट मिले। एक खुद का और दूसरा तिवारी जी का। तिवारी जी को भी दो वोट मिले। वे अपनी ससुराल से जाकर लड़े थे। जहां उनकी पत्नी, सास और ससुर का वोट था। जनादेश पर मंथन इस बात का था कि तीन में से तिवारी जी को वोट किसने नहीं दिया? ससुर ने वादा किया था कि वह वोट उनको ही देंगे, मगर ससुर उनसे हमेशा झूठ बोल कर वादा खिलाफी करते आए हैं। इस बात के साक्ष्य के तौर पर तिवारी जी ने बताया कि विवाह के समय भी उनकी पत्नी को गौर वर्णीय एवं गाय स्वभाव की बता कर ब्याह दिया था। दोनों ही बातें झूठी साबित हुईं। एक शक की सुई पत्नी पर भी घूमी कि उसी सुबह कुर्ता ठीक से प्रेस न करने पर तिवारी जी पत्नी पर भड़क गए थे और पत्नी ने उन्हें ऐसी नजर से देखा था जैसे कह रही हो कि देख लूंगी। शायद इस तरह ही उसने देख लिया हो। जनता भी इसी तरह कन्फ्यूज करती है।

मंथन खत्म हुआ। तिवारी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा घंसु को सौंपा और घंसु ने राष्ट्रीय सह अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा तिवारी जी को सौंपा। दोनों ने एक-दूसरे का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। फिर दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और प्रण किया कि पूरे जोश-खरोश से अब अगले चुनाव की तैयारी करनी है। ससुर और पत्नी से संबंध सुधारने होंगे तिवारी जी को एवं ससुर जी को अगली बार उनके गुणों को देखते हुए पार्टी से चुनाव लड़वाना होगा। फिर दोनों पुलिया से निकल कर पान की दुकान पर आ गए थे।

किसी ने तिवारी जी से चुटकी लेते हुए 12000 रुपये प्रति माह देने के वादे की याद दिला दी। घंसु उखड़ पड़े। अगर 12000 चाहिए थे तो हमें वोट देते। अब जाओ मांगो उन्हीं से, जिनको वोट देकर आए हो। जनता हतप्रभ थी कि ये एक ही दिन में क्या हुआ इनको कि कल तक सभी को भइया जी, बाबू जी, चाचा जी कहने वाले आज सबको गाली बक रहे हैं, जबकि हमने तो इनको आदेश भी नहीं दिया। जिनको आदेश दिया है वह तो दिल्ली चले गए हैं। अब पांच साल बाद ही मुलाकात होगी। तब तक अब जनता के आत्म मंथन का समय है कि जिन्हें आदेश दिया है उनका क्या कहर बरपेगा? मगर यही तो हर बार होता है। कहां कुछ बदलता है? आदत भी तो कोई चीज होती है, इतनी आसानी से कहां बदलती है!

(साभार: उड़न तश्तरी ब्लॉग में समीर लाल 'समीर')

मेलबाक्स

इंडिया पर हिंदुस्तान की जीत

अहंकारी और विशिष्ट बौद्धिक वर्ग की पराजय शीर्षक से लिखे अपने लेख में शंकर शरण ने 2019 के आम चुनाव में इंडिया पर हिंदुस्तान की जीत को रेखांकित किया है। देखा जाए तो आजादी के बाद से ही देश की सत्ता और बौद्धिक पत्रकारिता पर इंडिया ही काबिज रहा। पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू अभिजात्य वर्ग से आते थे, वह इंडिया में जीते थे और उन्होंने अभिजात्य वर्ग के इतिहासकारों और पत्रकारों को ही प्रश्रय दिया। पं. नेहरू की सोच को इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में उकेरा। आजादी की लड़ाई की कहानी भी अभिजात्य वर्ग की सोच के अनुसार ही देश को बताई गई। भारतीय दर्शन और शिक्षा के स्थान पर पश्चिम की शिक्षा और दर्शन को आगे बढ़ाया गया। उनके बाद इंदिरा और राजीव गांधी ने भी इंडिया को ही आगे बढ़ाया। वर्ष 2014 के बाद देश ने पहली बार सत्ता में हिंदुस्तान के उभार को महसूस किया। मोदी के नेतृत्व में देश ने पहली बार हिंदुस्तान को जिया। देश ने इसे चाहा और सराहा। इसीलिए देश ने 2019 में सत्ता में हिंदुस्तान को जारी रखने का जनादेश दिया है। देश के हित में यही जरूरी है कि देश की सोच देश की ही भाषाओं में प्रकट हो और देश के इतिहास तथा बौद्धिक लेखन में भी देश का ही दर्शन नजर आए। मोदी के नेतृत्व में यह संभव होगा ऐसा विश्वास देश ने किया है।

राजीव वार्ष्णेय, चंदौसी

हिंसा क्षम्य नहीं

चुनावी दौर में अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो कोई हिंसा नहीं हुई। केवल पश्चिम बंगाल में प्रत्येक चरण में किसी न किसी रूप में हिंसा हुई। अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं और हार-जीत भी हो चुकी है तो अब हिंसा का क्या औचित्य? लेकिन देश में कुछ अराजक लोग हैं जिनके अंदर राजनीतिक वैमनस्यता इस कदर बढ़ गई है कि वे एक-दूसरे की हत्या करने में संकोच नहीं कर रहे। किसी भी चुनाव में हर प्रत्याशी का काम होता है मतदाता को अपने पक्ष में करना और मतदाता का कर्तव्य बनता है कि वह अपने-अपने मनपसंद के उम्मीदवार को वोट करे। हर पार्टी का शुभचिंतक पुरजोर कोशिश करता है कि उसका ही उम्मीदवार जीते, लेकिन जब वह नहीं जीतता है तो इतना भी निराश नहीं होना चाहिए कि जीते उम्मीदवार या उसके शुभचिंतक की हत्या कर दी जाए। यह किसी भी प्रकार से लोकतंत्र को परिभाषित नहीं करता। चुनाव में हार या जीत होती रहती है, इस बात का ख्याल करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। अगर किसी को हार बर्दाश्त नहीं होती तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव जीतने या हारने के बाद हिंसा कतई क्षम्य नहीं है। हिंसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

दिल साफ करे पाक

पाकिस्तान की मोदी को जीत की बधाई देना अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को अपना दिल भी साफ करना चाहिए। भारत ने जब भी उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसने इसके पीठ में छुरा भोंका है। अगर वह भारत से साथ संबंध सुधारना चाहता है तो सबसे पहले अपने यहां पल रहे आतंकियों को सरंक्षण देना बंद करना होगा। उसे हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद और दूसरे खतरनाक आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए। इस तरह अगर वह कुछ सकारात्मक कदम उठाए तो दोनों देशों के संबंधों में सुधार की गुंजाइश बन सकती है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

उपवास का महत्व

दुनिया के अधिकांश धर्मों में किसी न किसी रूप में उपवास का अपना एक महत्व बताया गया है। इस्लाम में इसी उपवास को रोजा कहते हैं। रमजान मुसलमानों का सबसे पाक मास कई कारणों से विशिष्ट होता है। रोजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल भूखे-प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि प्रत्येक मुसलमान के जीवन के मूल उद्देश्य के आमंत्रण के साथ-साथ अनुशासन और सत्य के लिए एक साल अन्य 11 महीनों के लिए अभ्यास है। दरअसल रोजेदार भूखा और प्यासा रह कर गरीबों और वंचितों की स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि रमजान इबादत के साथ-साथ सत्य के मार्ग पर चलने, गरीबों की मदद करने और अपने अंदर की बुराइयों को त्यागने के लिए सबसे खास मास है। यही रमजान के रोजे का सार्थक पहलू है।

प्रेमपाल सिंह, मोहन नगर, पलवल

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 23359961-62, नोएडा कार्यालय: 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।